

## Newspaper Clips

August 22, 2014

**Asian Age, ND**

**22/08/2014**

**P-3**

### **PREZ, PM TO MEET IIT HEADS OVER RANKINGS**

**AGE CORRESPONDENT**

**NEW DELHI, AUG. 21**

President Pranab Mukherjee will meet heads of IITs on Friday to discuss a national framework on ranking of institutes. The meeting is also expected to discuss ways to enable students from the Northeast do a part of their programme from IITs and other premier institutes, earning credit points.

The conference with the chairmen, board of governors and directors of IITs at Rashtrapati Bhavan is the first such initiative by the President.

Sources in the human resource development ministry stated that Prime Minister Narendra Modi and HRD minister Smriti Irani will also be present at the conference. The President is the visitor of these premier institutes.

**Indian Express ND**

**22/08/2014**

**P-12**

### **PRESIDENT TO HOLD CONFERENCE OF IITs TODAY**

**NEW DELHI:** President Pranab Mukherjee, in his capacity as the Visitor of all Indian Institutes of Technology (IITs), will host a conference of chairmen, boards of governors and directors of IITs at Rashtrapati Bhavan Friday. PM Narendra Modi and Union HRD Minister Smriti Irani will also participate in the meet. This is the first time that a conference of this nature is being convened by the President. Twenty-nine chairmen, members of boards of governors and IIT directors will participate. The event's agenda includes deliberating on steps needed to improve global ranking of IITs. **ENS**

**Jansatta ND 22/08/2014 P-5**

# आईआईटी के प्रमुखों से आज मिलेंगे राष्ट्रपति

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 21 अगस्त। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी शुक्रवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के प्रमुखों से मिल कर संस्थानों की रैंकिंग के राष्ट्रीय स्वरूप पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति आईआईटी के प्रमुखों से इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों को किस तरह आईआईटी और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से अपने कार्यक्रम का एक हिस्सा पूरा करने और क्रेडिट प्वाइंट हासिल करने के योग्य बनाया जाए। राष्ट्रपति भवन में सभी आईआईटी के अध्यक्षों, संचालक मंडल और निदेशकों के सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रपति की एक अनोखी पहल है। राष्ट्रपति

आईआईटी के विजिटर होते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी भी इस सम्मेलन में मौजूद होंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस सम्मेलन से पहले गुरुवार को केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और आईआईटी के निदेशकों ने मुलाकात की ताकि रैंकिंग के स्वरूप का मसौदा तैयार किया जा सके और इस बाबत आम सहमति बनाई जा सके। राष्ट्रपति अक्सर इस बात पर चिंता जताते रहे हैं कि शीर्ष शिक्षण संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग सूची में आईआईटी जैसे भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों को जगह नहीं मिल पाती है।

**Virat Vaibhav ND 22/08/2014 P-5**

# आईआईटी के प्रमुखों से आज मिलेंगे राष्ट्रपति

भाषा

नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रमुखों से मिलकर संस्थानों की रैंकिंग के राष्ट्रीय स्वरूप पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति आईआईटी के प्रमुखों से इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों को किस तरह आईआईटी एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से अपने कार्यक्रम का एक हिस्सा पूरा करने और क्रेडिट प्वाइंट हासिल करने के योग्य बनाया जाए। राष्ट्रपति भवन में सभी आईआईटी के अध्यक्षों, संचालक मंडल और निदेशकों के सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रपति द्वारा की गई एक अनोखी पहल है। राष्ट्रपति

आईआईटी के विजिटर होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस सम्मेलन में मौजूद होंगे।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि इस सम्मेलन से पहले गुरुवार को केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और आईआईटी के निदेशकों ने मुलाकात की ताकि रैंकिंग के स्वरूप का मसौदा तैयार किया जा सके और इस बाबत आम सहमति बनाई जा सके। राष्ट्रपति अक्सर इस बात पर चिंता जताते रहे हैं कि शीर्ष शिक्षण संस्थानों की वैश्विक रैंकिंग सूची में आईआईटी जैसे भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों को जगह नहीं मिल पाती है।

## आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स मोटे सैलरी पैकेज छोड़कर ले रहे हैं रिस्क

### 26 लाख का पैकेज छोड़ा

अपने इनोवेटिव आईडियाज पर खुद का काम शुरू करने का ट्रेंड बढ़ा, इंटरनेट क्रांति के बाद नया बिजनेस शुरू करने की लागत हुई है कम



### एडवेंचर लवर्स की नेटवर्किंग

आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग कर चुके दिव्य प्रताप सिंह और सचिन गोयल ने 12 लाख रुपये से ज्यादा का पैकेज छोड़कर इस वेबसाइट को शुरू किया है। खुद का स्टार्टअप टूर्नामेंट हो या एक एडवेंचर ट्रिप ऑर्गनाइज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, यहाँ सब इंतजाम है। यह एक इवेंट को ऑर्गनाइज करने के लिए पूरा आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर देती है। यहाँ पर आप एक जैसे सोच रखने वाले लोगों को इनवाइट भी कर सकते हैं। 365होपस.कॉम नाम की इस वेबसाइट में सोशल प्लेटफॉर्म भी मिलता है। दिल्ली में कई स्टार्टअप एक्टिविटीज और देश भर में एडवेंचर स्पॉट्स के इवेंट्स की जानकारी मिलती है। ईस्ट दिल्ली के लक्ष्मीनगर में रहने वाले दिव्य बिजनेस शुरू करने से पहले लंदन की एक ब्लूटूथ बनाने वाली कंपनी में काम करते थे। दिव्य बताते हैं कि उन्होंने वेबसाइट से देश भर की 100 एडवेंचर स्पॉट्स कंपनियाँ, दिल्ली की 20 और स्पॉट्स एक्टिविटीज की 15 कंपनियाँ जुड़ चुकी हैं।

# ‘अपना IDEA अपना काम’

दिल्ली के आईआईटी से अब सिर्फ इंजीनियर ही नहीं निकल रहे हैं बल्कि ‘बिजनेसमैन’ भी बाहर आ रहे हैं। आईआईटी कॅम्प्लिट करने के बाद अपना बिजनेस शुरू करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या भी बढ़ रही है। लाखों के पैकेज तुकराकर स्टूडेंट्स अपने इनोवेटिव आईडियाज के दम पर खुद अपना काम शुरू करने का रिस्क उठा रहे हैं। यह ट्रेंड पहले भी था लेकिन इंटरनेट क्रांति के बाद काफी बढ़ा है। फ्लिपकार्ट, जॉबिंग, रनैपडील जैसे उदाहरण स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ रिस्क टेकर्स से बात की राहुल मानव ने :



### वेडिंग प्लानिंग का नया कॉन्सेप्ट

2011 में सिविल इंजीनियरिंग में आईआईटी दिल्ली से ग्रेजुएशन कर चुके मनीष गोयल और 2012 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ग्रेजुएट हिमांशु कपसिमे ने एक वेडिंग प्लानिंग वेबसाइट को शुरू की है। हिमांशु ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 8 लाख रुपये का पैकेज

छोड़कर अपने सौनियर मनीष के साथ मिलकर बिजनेस शुरू करने का फैसला किया तो लोगों ने उन्हें रिस्क नहीं लेने की सलाह दी, लेकिन वे अपने फैसले पर कायम रहे। इस वेबसाइट की मदद से लोगों को मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, हनीमून पैकेज, कोरियोग्राफर,

शशांक सिंगला ने आईआईटी दिल्ली से 2010 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने एक काम शुरू किया था, जिसे एक साल में बंद कर दिया। फिर एक एमएनसी में जॉब की, जहाँ उन्हें 26 लाख का पैकेज मिला था। लेकिन कुछ वक्त बाद उन्होंने नौकरी छोड़कर अपने वैचमेट रोकेश सहगल के साथ मिलकर रिक टेक्नॉलजी कंपनी शुरू की है। उन्होंने ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी मदद से ऑफिस में बैठे ही इंटरनेट को यूज करके कंपनियाँ मॉल्स और रेस्टॉरंट में लगी उनकी एलसीडी स्क्रीन में आ रहे एड और दूसरी जानकारी को कंट्रोल कर सकती है। रोकेश बताते हैं आमतौर पर कई जगहों में कंपनी के लोगों को जाकर स्क्रीन में पेन ड्राइव फिट करनी पड़ती थी। शशांक कहते हैं कि बड़ी कंपनियों में अच्छे पैकेज तो मिलते हैं लेकिन वेल्थ नहीं मिलती, इसलिए हमने फैसला किया कि खुद का बिजनेस शुरू करके देश की तरक्की में अपना रोल अदा करेंगे और दूसरों को जॉब प्रोवाइड कराने में मदद करेंगे।



फूलवाले जैसे वेडर्स की प्रोफाइल मिलेगी। यानी इस वेबसाइट पर खुद शादी की प्लानिंग कर सकते हैं। शादी सागा नाम से इस वेबसाइट में कई एक्सपर्ट्स आपको मिल सकते हैं। हिमांशु कहते हैं कि वेबसाइट में कपल्स खुद की वेडिंग वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें वे अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी स्टोरीज शेयर कर सकते हैं। 2000 कपल्स ने खुद की वेडिंग वेबसाइट बनाई है।

## IIT-Delhi professor invents waterless and odourless urinals



Dr Chariar displays a membrane tap, which is used in the waterless odourless urinals innovated by his team.

<http://www.mid-day.com/articles/iit-delhi-professor-invents-waterless-and-odourless-urinals/15544191>

The idea first germinated with the need to conserve fresh water, especially in areas where it cannot be re-used, like in restrooms. “We realised that restrooms are using a lot of fresh water, even when there is no real need. In our country, we still don’t have technology that can make contaminated water fit for re-use. So, we felt the need for water-free urinals,” said Dr V M Chariar, a professor of rural development and technology at IIT-Delhi.

You don’t need water to flush away waste in these urinals, which can be used in homes, institutions and public spaces. Four thousand such urinals have already been installed across the country, using the technology developed by Dr Chariar. While only males can use Chariar’s urinals at present, women-friendly urinals will be launched by November this year.

In terms of design, the urinals look just like conventional urinals, and can be used in the same manner. However, they save close to 1,70,000 litres of water, says Dr Chariar.

“Not only do these urinals reduce usage of fresh water, they lead to smaller quantities of sewage,” added Dr Chariar. These urinals do not need expensive plumbing accessories.

The dry and touch-free operation reduces the chance of spreading communicable diseases. “An added advantage is the presence of an odour trap mechanism, using sealant liquid, microbial control and curtain valves

fitted to waterless urinals that help prevent odour developing inside the drainage lines,” he added.

“This technology will cost one-fifth of what similar technologies cost in our country. Also, maintenance is inexpensive. We are thinking of acquiring funds from UNICEF in order to ensure that the project is installed in full force,” he said.

More than funding, Dr Chariar thinks there is immense need for awareness and informative campaigns in order to ensure that the project is implemented in totality. “Sanitation in India is a complex issue, and in order to ensure proper installation of these urinals, we also need to make the public more aware of high-standard sanitation facilities. And, the government will have to play a much bigger role.”

Dr Chariar is already in talks with the ministry as well as the Indian Railways, to install these waterless urinals in public spaces, including railways.

“We can see that many corporate firms are also looking to invest funds into this sector; all they need is proper planning. We have our plans and we only need to ensure that it is implemented as well as maintained well in the future,” he added. - See more at: <http://www.mid-day.com/articles/iit-delhi-professor-invents-waterless-and-odourless-urinals/15544191#sthash.rvDTqicf.dpuf>

Economic Times ND 22/08/2014 P-4

# HRD Ministry Sides With UGC in Course Clash with IIT Kharagpur

IIT told to identify mismatch between UGC and its course and work for students' good

Ritika Chopra  
@timesgroup.com

**New Delhi:** In what could revive the age-old confrontation between the government and the IITs regarding the latter's autonomy, the human resource development ministry has endorsed the University Grants Commission's attempt at exercising its authority over the elite engineering schools.

IIT Kharagpur — the oldest of the 16 IITs — had recently shot off a letter to the government protesting a recent circular from the higher education regulator asking all the institutes to align their courses with pattern approved by UGC.

In his letter to higher education secretary Ashok Thakur, IIT Kharagpur director Partha Chakrabarti had asserted in that IITs are governed by their own Act of Parliament and are, therefore, outside the purview of the UGC.

## Prez to Discuss Ranking with IIT Heads Today



**NEW DELHI:** President Pranab Mukherjee will meet IIT heads here today to discuss a framework on ranking of institutes and enabling students from NE do a part of their programme from IITs and other premier institutes and earn credit points. The conference with the chairmen, governors and directors of IITs at Rashtrapati Bhawan would be the first such initiative by the President.

The ministry, however, is learnt to have backed regulator's move and told Chakrabarti that it will be more "appropriate" for him to identify the mismatch between UGC-specified degrees and the ones offered by his institute and work towards a solution in the students' interest.

Justifying its decision to side with the UGC, the government has observed that IIT Kharagpur was try-

ing to stretch IITs' powers to 'institute courses of study' to 'institute their own degrees'.

Chakrabarti didn't comment on the issue as he had not read the ministry's reply to his letter yet.

The UGC letter to all higher education institutions stems from the new government's decision to roll back Delhi University's four-year undergraduate programme.

This programme was withdrawn on the ground that it does not fit UGC's approved nomenclature of degrees. This led the regulator to correct discrepancies elsewhere.

The attempt, however, has had its share of controversies with the Indian Institute of Science, Bangalore, openly opposing UGC's directive to tweak its four-year programme to suit the regulator's approved pattern. Now IITs are unhappy over UGC's "overstepping".

The dean of academic affairs at IIT Kanpur, which offers a four-year undergraduate programme in bachelors in physics, chemistry, mathematics and economics, told ET that the institute is not aware of the ministry's stand on the matter and hence hasn't taken any decision regarding making any changes.

The matter could come up for discussion at a meeting of IIT heads with President Pranab Mukherjee, PM Narendra Modi and HRD minister Smriti Irani on Friday.

HINDU ND 22/8/2014 P-1

# IITs told to toe UGC line on degrees

Anita Joshua

**NEW DELHI:** The controversy over Delhi University's Four-Year Undergraduate Programme (FYUP) has opened up a fresh fault line with the University Grants Commission asking the Indian Institutes of Technology to ensure that their degrees conform to the Commission's July 5 gazette notification on approved courses.

This could trigger a controversy as the IITs insist they were set up by a separate Act of Parliament and, therefore, not governed by the UGC Act. But the Human Resource Development (HRD) Ministry has

taken the view that the provisions of the UGC Act, 1956, and the Institutes of Technology Act, 1961, should be "construed in a harmonious manner rather than to the exclusion of the other."

The Ministry formulated its position after the director of IIT Kharagpur, Pratha Prathim Chakraborty, wrote to the Higher Education Secretary seeking intervention in the matter. While many of the IITs decided to ignore UGC's communication,

Prof. Chakraborty wrote back contesting it. His letter underscored the fact that IITs are governed by their own Act of Parliament and

empowered to institute "courses of study" without seeking the approval of the UGC.

## IIT autonomy

Stating that there was some confusion within the UGC regarding autonomy and powers of the IITs to institute their own degrees and courses of study, IIT Kharagpur asked the Ministry to clarify this to the Commission which issued the gazette notification after the controversial rollback of Delhi University's FYUP.

Responding to Prof. Chakraborty's letter, the Ministry said IIT Kharagpur should list the various

degrees that may not be in conformity with the list of UGC specified degrees. "The exact mismatch between IIT Kharagpur degrees and the UGC-specified degrees may have to be reviewed jointly" by them and an appropriate solution worked out considering the student interests at stake.

As for Prof. Chakraborty's contention that IITs are empowered by the Institutes of Technology Act to institute "courses of study," the Ministry's opinion is that this does not imply degrees since both are used at separate places in the IIT Act, 1961, without any expressed equivalence.

MINT ND 22/08/2014 P-24

Deccan Herald, ND  
22/08/2014 P-6

# IITs need UGC nod to open new programmes

BY PRASHANT K. NANDA  
prashant.n@livemint.com

NEW DELHI

**A**pex education regulator the University Grants Commission (UGC) has told the Indian Institutes of Technology (IITs) they will need to get its approval for opening or fixing the tenure of new degree programmes, drawing protests from IIT Kharagpur.

The UGC has sent letters to all the 16 IITs, along with a gazette notification of 5 July in which it has mentioned the approved courses. The move follows UGC's face-off with Delhi University over the varsity's four-year undergraduate course.

The order means that if, for instance, an IIT wants to start a four-year undergraduate course, it will need the prior approval of UGC. IIT Kanpur already has such a programme. IITs are unhappy about the UGC circular, and some have told the human resources development (HRD) ministry about it, at least two government officials said.

"If a university wishes to award a degree other than the one specified by UGC or change the duration of the course" specified as minimum in gazette notification, "it shall approach UGC for approval six months prior to starting the programme with full justification on the course to be started", the circular said.

A letter written by IIT-Kharagpur to the higher education department said since IITs were created by an Act of Parliament, they are not governed by UGC and do not need approval to "institute course of study".

Though *Mint* could not reach IIT Kharagpur immediately, a senior administrator at one of

the older IITs confirmed the development and said all the IITs will take up the matter in their meeting with President Pranab Mukherjee on Friday.

Mukherjee is meeting representatives of all IITs to discuss how they can contribute to the development of the nation through community engagements. HRD minister Smriti Irani and senior officers of the ministry will be present.

The ministry has reviewed the position of both the UGC Act 1956 and the IIT Act 1961, and is believed to take the stand that both should be seen in a "harmonious manner rather than to the exclusion of other", said one of the two officials cited above.

"It will be appropriate at this stage if director of IIT Kharagpur lists various degrees he feels are not in conformity with the list of UGC specified degrees," an internal ministry note said. The ministry is understood to have advised that the position of both have to be reviewed jointly by IIT Kharagpur and UGC and an appropriate solution needs to be worked out considering the "students' interest at stake".

During its face-off with Delhi University, the apex regulator had said all institutes of higher education have to comply with the country's education policy which advocates a 10+2+3 formula. Only those courses which are approved by UGC to exceed that tenure are allowed. It means IITs will not face any problem in their four-year B-Tech or two-year M-Tech programmes as these are valid under the UGC Act but will have to seek UGC approval if they want to open new degree courses on their own or change the duration of the already approved programmes.

## IITs reject UGC diktat on course format

Prakash Kumar

**NEW DELHI:** The Indian Institutes of Technology (IITs) have objected to the University Grants Commission's (UGC) directive that they must stick to the duration and specifications of degree courses, recently dictated by it.

They have also questioned the powers and jurisdiction of the higher education regulator over IITs.

In a letter to the Human Resource Development Ministry recently, IIT-Kharagpur has expressed surprise at the UGC's directive, noting that all the 16 premier technical institutes are governed by an Act of Parliament and their Council, not the UGC.

IIT Kharagpur director P P Chakrabarty has asserted that all the IITs are empowered to "institute courses of study" and they do not need to seek any approval of the UGC.

Noting that there was "some confusion" within the UGC about the autonomy and powers of the IITs to institute their own degrees and courses of study, he urged the Ministry that "this may be clarified" to the higher education regulator.

Days after forcing Delhi University to roll back a four-year under-graduate programme (FYUP), the UGC came up with a gazette notification specifying the nomenclature of all the higher education programmes and duration of degree courses.

It also wrote to all the higher educational institutions, including IITs, asking them to stick to the notification and restructure the programmes not in conformity with it.

In its communication, the Commission also threatened of "appropriate" action, if any institute deviates from the nomenclature of programmes and duration of degree courses prescribed by it.

Many IITs are offering courses which are not in sync with the format prescribed by the UGC. IIT-Kharagpur offers five-year integrated MSc programme in six subjects, including applied geology. IIT-Madras offers five-year BS and MS dual degree programmes.

DH News Service



## HRD Min favours joint review of IIT degrees by UGC, IITs

[http://www.business-standard.com/article/pti-stories/hrd-min-favours-joint-review-of-iit-degrees-by-ugc-iits-114082101304\\_1.html](http://www.business-standard.com/article/pti-stories/hrd-min-favours-joint-review-of-iit-degrees-by-ugc-iits-114082101304_1.html)

The HRD Ministry has favoured a joint review of [IIT](#) degrees both by the UGC and the [premier](#) technical institute following a fresh controversy over the commission's directive to align IIT courses along the lines of those recognised by it.

The Ministry has suggested both to hammer out an "appropriate solution" as University Grants Commission maintains that some of the IIT programmes are not in conformity with those recognised by it, officials said.

IIT-[Kanpur](#) offers four-year undergraduate programmes such as Bachelors in Science (BS) in Physics, Chemistry, Mathematics and Economics, while UGC's list of recognised degrees only allows for a four-year BSc degree.

The UGC directive to IIT-Kharagpur director has come as a "surprise" to the IITs which insist that they are not governed by the UGC Act but the Act of [Parliament](#) and IIT Council and therefore are empowered to "institute courses of study" without the need to seek approval of the Commission.

The direction from the UGC, the apex regulatory body governing higher education in the country, was sent to director of IIT Kharagpur, months after it asked Delhi University to scrap its four-year-undergraduate programme and sent instructions to some other institutes including Indian Institute of Science (IISc) Bangalore to align their courses.

The Commission had on July 5 issued a gazette notification after the Delhi University controversy listing out all the recognised degrees.

With IITs asking for a clarification about the powers and the autonomy enjoyed by it to institute own degrees, the Ministry has opined that the provisions of the UGC Act 1956 and IIT Act 1961 should be "construed" in a harmonious manner rather than exclusion of the other.

It has also underlined the fact that the expression 'degrees' is not defined in the IIT Act, 1961.

Therefore, "It would be more appropriate at this state if the Director IIT Kharagpur lists the various degrees which he feels are not in conformity with the list of UGC specified degrees.

"The exact mismatch between IIT Kharagpur degrees and the UGC specified degrees may have to be reviewed jointly by IIT Kharagpur and UGC and an appropriate solution worked out considering the student interests at stake," the Ministry has suggested.

## STATESMAN ND 22/8/2014 P-6

# IIT-Kharagpur locks horns with UGC

STATESMAN NEWS SERVICE

New Delhi, 21 August

The University Grants Commission and IIT Kharagpur are locked in a tussle following a gazette notification issued by UGC regarding degrees offered by universities. IIT Kharagpur, however, maintained that it is governed by its own Act, Institutes of Technology Act.

The notification dated 5 July asked universities to have degrees that are "generally recognised, globally acknowledged and widely

accepted". On 12 July, it was followed up with letters to the IITs, including IIT Kharagpur.

The director of IIT Kharagpur, in his letter to the Human Resource Development Ministry, said the UGC letter has come as a surprise because IITs are not governed by the UGC Act but by the Act of Parliament and IIT Council, the IITs are empowered to frame 'courses of study' without the need to seek approval of the UGC. He said there is some confusion within the UGC regarding the autonomy and powers of the IITs to institute

their own degrees and courses of study. He has requested the HRD ministry to clarify this to the UGC.

The HRD ministry has taken the stand that the UGC Act, 1956, is as much an Act of Parliament as is the Institutes of Technology Act, 1961.

Seeking to resolve the matter, the HRD ministry has observed that the provisions of the UGC Act 1956 and IIT Act 1961 are to be construed in a harmonious manner rather than to the exclusion of the other.

## Hindustan Times, ND 22/08/2014 P-8

# Govt backs UGC: IITs can grant only recognised degrees

HT Correspondent

letters@hindustantimes.com

**NEW DELHI:** In what is turning out to be a confrontation between the Indian Institute of Technologies (IITs) and the University Grant Commission (UGC) on degrees issued by the premier technical institutions, the government has backed the latter saying the IITs can issue only those degrees recognised by the UGC.

In a letter written to IIT Kharagpur which had raised objection to the UGC's direction

to all universities including the IITs to roll back courses that are not recognised by it, the human resource development (HRD) ministry said it had stretched its power under the IIT Act 1961, an act of Parliament under which IITs are governed.

Suggesting a way out of the confrontation, the ministry asked both the IITs and UGC to hammer out an "appropriate solution" and list out the degrees that are not in conformity with the UGC regulations.

The UGC, an apex regulatory body for higher education in the

country, had shot off a letter to all institutions of higher learning on July 12 asking them to conform to degrees recognised by it saying unspecified degrees could lead to a barrage of litigation.

UGC's letter had come in the backdrop of the Delhi University four-year undergraduate programme controversy, after which it notified all the recognised degrees.

The UGC had recently forced Indian Institute of Science (IISc) Bangalore to change the name of its course under the same regulation.



■ IIT Kharagpur had objected to the UGC's direction to roll back courses not recognised by the universities.

ARVIND YADAV/HT FILE

MINT ND 22/08/2014 P-24

# Five new IITs, six IIMs likely to become operational by next year



**Fresh provision:** The Common Admission Test conducted by the IIMs and the Joint Entrance Examinations conducted by the IIT system will make provisions for admission to all the new institutes, say officials.

By PRASHANT K. NANDA  
prashant.n@livemint.com

NEW DELHI

The process of setting up five Indian Institutes of Technology (IITs) and six Indian Institutes of Management (IIMs) promised in the Union budget is under way, amid lingering concerns that this would dilute the brand value of the elite institutions and worsen their resource crunch.

The human resources development (HRD) ministry has discussed the proposal to set up the new institutes with the finance ministry twice in the last one month and the centre has written to the states where they are proposed to come up, two government officials familiar with the matter said. The schools will open next year and initially function from temporary campuses, said the officials, who declined to be named.

"There is always a need for more quality institutions and all the new IITs and IIMs will be operational from the coming year. It's better to start them early," said one of the two officials cited above. "The HRD ministry will float a cabinet note soon—may be in the next two to three months," the official said.

The Union budget presented by finance minister Arun Jaitley had proposed IITs in Jammu and Kashmir, Chhattisgarh, Goa, Andhra Pradesh and Kerala, and IIMs in Himachal Pradesh, Punjab, Bihar, Odisha and Maharashtra. The sixth IIM will come up in Andhra Pradesh as part of the Andhra Pradesh Reorganization Bill. The budget allocated an initial sum of ₹500 crore for the current fiscal year for these institutes.

Once all of them open their doors, India will have a total of 19 IIMs and 21 IITs.

The second government official said the Common Admission Test (CAT) conducted by the IIMs and the Joint Entrance Examinations (Advanced) conducted by the IIT system will make provisions for admission to all the new institutes.

"Recently, the government of India has proposed six new IIMs in the country. Interested candidates may also choose postgraduate programmes (PGP) in these new locations, as well, under the section 'Apply to the Proposed New Six IIMs,' the CAT registration guideline document has underlined.

This year's CAT is scheduled for 16 and 22 November. The results will be announced in the third week of December for the admission to all IIMs in 2015.

However, the sudden increase in the number of these elite institutes has sparked

concern in some quarters.

"There is certainly a need for more IITs and IIMs in the country, but they are coming too many too quickly. There was huge gap between when the older ones came up and the new ones are coming up. Instead of so many, so quickly, it could have come one by one over the last few decades. The government now has to work to reduce the risk (of failure) by way of leveraging technology, quality content and improved delivery," said Ajay Kela, chief executive of Wadhvani Foundation and an alumnus of IIT-Bombay.

The previous government had set up seven new IIMs and eight new IITs between 2008 and 2011, but most of these are operating from make-shift campuses and face challenges in terms of their quality of teaching and research. They are also short of teaching staff by 20-40%, as per official statistics.

The second official said the government is allocating more money to the new IIMs and IITs so that many of them shift to their permanent campus "within a year or so".

"The new IITs and IIMs announced this budget will have to come up on temporary campuses, but the ministry is making all efforts to shift the older ones that became operational post-2008 to their permanent campuses. For example, the new IITs are getting a little over ₹1,200 crore each this financial year to expedite their work instead of the earlier plan to allocate around ₹950 crore each," the official said.

However, the details are being worked out on the possible number of student intakes, and the streams with which these institutions will be operational from 2015.

Currently, more than half a million students vie for around 9,600 IIT seats, while nearly 200,000 candidates compete for less than 3,500 IIM seats.

# Rush of PPOs at IITs Hints at Good Year for Graduates

At IIT Bombay, job announcement forms given by cos are double that of last year

Devina Sengupta & Sreeradha D Basu

**Mumbai:** The first flush of pre-placement offers (PPOs) now being handed out at India's leading IITs are pointing to a coming bumper placement season this year.

At IIT Bombay, job announcement forms submitted by companies are already double of what was seen at the same time last year. The number of PPOs at other IITs is also rising, offering yet another piece of evidence of a resurgent job market.

Companies make pre-placement offers based on performance of candidates who have interned with them. Many companies like Goldman Sachs and RIL now use this route more, as it helps them gauge candidates better, over longer periods of time and in real work situations. Such internships at IITs end in August and the first PPOs are trickling in now. The flow will gather momentum by mid-September/October and will continue till December 1, when the campus placement season begins.

Facebook started its campus hiring this year by offering international posts to students of IIT Bombay and IIT Kharagpur. Although the social networking company has not disclosed salary details to the colleges, it is expected to offer at least \$120,000, which was last year's package.

Microsoft has also rolled out PPOs at IITs, after offering ₹79.5 lakh per annum pay packets for Redmond-based posts at non-IIT campuses recently. Deloitte is offering ₹21.3 lakh for domestic profiles.

Others who have offered PPOs, include Schlumberger, Directi, Adobe, Reliance, Shell Technology, Cadbury, Qualcomm, Deutsche Bank, Credit Suisse, Mitsubishi Heavy Industries, HUL, ITC, Samsung, VMware, Samsung Research, LinkedIn, VizExperts, Works Application, Goldman Sachs (Tech) Intuit, Futures First and P&G. The companies can come again for campus placements to hire more.

Companies also use PPOs to get an early advantage in the war for talent at the placement season in campuses.

"This year looks very promising. The political & economic ecosystem looks very supportive," said Mohak Mehta, placement manager at IIT Bombay. Mehta said recruiters from Japan, Singapore, South-

## Jobs Galore



Institute	PPOs so far	PPOs same period last year	Total PPOs last year	Cos which offered PPOs so far this year
IIT Bombay	30	19	90	Microsoft, Shell, Qualcomm, Intuit, Futures First, Deutsche Bank, P&G, Samsung
IIT Kharagpur	51	Less than 51	126	Facebook, Microsoft, Samsung R&D, LinkedIn, VizExperts, Credit Suisse, Shell Technology Centre, Works Application, Qualcomm, Goldman Sachs (Tech Division)
IIT Madras	32	Data unavailable	67	Shell Technology Centre, LinkedIn, Credit Suisse, Deutsche Bank, Adobe, Samsung R&D, HUL, Microsoft
IIT Roorkee	29	23	57	Microsoft, Directi, D.E. Shaw India Software, Goldman Sachs (Tech Division), Qualcomm India, Shell Technology Centre, Adobe Research India, Samsung R&D
IIT Kanpur	36	30	45	Qualcomm, Deutsche Bank, Microsoft, Adobe, Credit Suisse, Mitsubishi Heavy Industries, Reliance, HUL, ITC, Samsung, Schlumberger, Shell, VMware
IIT Ropar	6	2	2	Arista Networks, Amazon, Microsoft

Source: Institute placement cell; in some cases, certain branches of cos have hired separately so names may vary

East Asia & Middle-East have shown special interest this year. The college has received 30 PPOs and is not expected to take long to cross last year's total of 90 PPOs.

Monday's count of PPOs at IIT-Kharagpur shows 51 offers, said Sudhirkumar Barai, professor-in-charge, training and placement of the institute. Expecting a return of big hiring, IIT Madras and IIT Roorkee have made changes in their placement methods to fit in more companies. IIT Roorkee will introduce parallel slot system where three slots of six companies each will hold interviews on the first day. So, 18 companies can pick their employees simultaneously compared with mere 3-4 recruiters per day hiring last year.

"This reduces hassles of managing company preferences for initial slots and more hires can take place. We did a dry

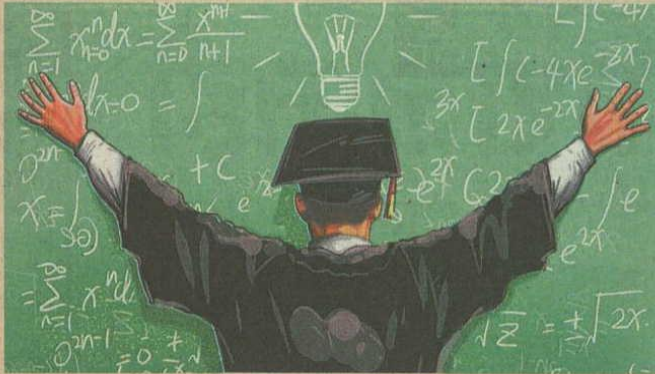
run of parallel slot system during internship placements this year and it was a success," said NP Padhy, professor-in-charge, Training and Placement IIT Roorkee.

IIT Madras will start their placements in 'graveyard shifts' from 12 at night to 7 am on December 1. This will be done to navigate international time zones and have international companies recruit via calls and Skype. IIT Madras has bagged 32 PPOs from Shell, LinkedIn, Deutsche Bank, Credit Suisse, HUL and Microsoft.

IIT Kanpur says a larger draw from startups and international posts will be on the cards this year and has already received 36 pre-placement offers compared with a total of 45 rolled out in 2013. The older IITs of Madras, Kanpur, Bombay, Kharagpur have an average of 1,000 students each registered for placements.

दिसंबर में प्लेसमेंट सीजन शुरू होने से पहले  
बेहतर स्टूडेंट्स को हायर करने की होड़

# IIIT में सुपर हिट रहा प्री-प्लेसमेंट ऑफर्स का फर्स्ट राउंड



[ देविना सेनगुप्ता | मुंबई ]  
देश के बड़े आईआईटी कैंपस में प्री-प्लेसमेंट की पहली खेप से संकेत मिल रहे हैं कि इस साल प्लेसमेंट सीजन में स्टूडेंट्स के हाथ बंपर ऑफर आएंगे। आईआईटी-मुंबई में कंपनियां पिछले साल से लगभग दोगुने जॉब अनाउंसमेंट फॉर्म अभी ही जमा कर चुकी हैं। दूसरे आईआईटी में भी प्री-प्लेसमेंट ऑफर (पीपीओ) की संख्या बढ़ी है। इससे जॉब मार्केट में बहार आने की बात पक्की होती दिख रही है।

कंपनियां अपने साथ इंटरशिप कर चुके कैंडिडेट्स की परफॉर्मेंस के आधार पर प्री-प्लेसमेंट ऑफर देती हैं। गोल्डमैन सैक्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कई कंपनियां ऐसा तरीका ज्यादा आजमाने लगी हैं। इससे कंपनियों को ज्यादा वक्त गंवाए बिना सही कैंडिडेट चुनने में सहाय्य मिलती है। आईआईटी में इंटरशिप पीरियड अगस्त में खत्म होता है और कंपनियों के पीपीओ भी आने शुरू हो गए हैं। सितंबर मध्य या अक्टूबर से लेकर 1 दिसंबर तक इसमें तेजी आएगी। उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट का सीजन शुरू होगा।

इस साल फेसबुक की कैंपस हायरिंग आईआईटी-बॉम्बे और आईआईटी-खड़गपुर से शुरू हुई है। कंपनी इन स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल पोस्ट ऑफर

कर रही है। सोशल नेटवर्किंग कंपनी ने अभी सैलरी पैकेज के पते नहीं खोले हैं, लेकिन उम्मीद है कि वह कम से कम 1,20,000 डॉलर ऑफर कर सकती है, जो पिछले साल का पैकेज है।

माइक्रोसॉफ्ट भी अपने पीपीओ के साथ आईआईटी में पहुंच चुकी है। इससे पहले कंपनी नॉन-आईआईटी कैंपस में सालाना 79.51 लाख रुपये का पैकेज ऑफर कर चुकी है। ये ऑफर कंपनी ने रेडमंड में मौजूद पोस्ट्स के लिए दिए थे। डेलॉयट अपने डोमेस्टिक प्रोफाइल के लिए आईआईटी ग्रेजुएट्स को 21.3 लाख रुपये का पैकेज ऑफर कर रही है।

पीपीओ ऑफर करने वाली दूसरी कंपनियों में श्लामबर्जर, डायरेक्ट, एडोबी, रिलायंस, शेल टेक्नोलॉजी, कैडबरी, क्वालकॉम, डोएचे बैंक,

क्रेडिट सुईस, मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज, एचयूएल, आईटीसी, सैमसंग, सैमसंग रिसर्च, लिंकडइन, विजएक्सपर्ट्स, वर्क्स एप्लिकेशन, गोल्डमैन सैक्स (टेक) इन्डुइट, फ्यूचर फर्स्ट और पीएंडजी

हैं। ये और ज्यादा हायरिंग के लिए कैंपस सेलेक्शन के दौरान भी आ सकती हैं। कंपनियां पीपीओ का इस्तेमाल कैंपस सेलेक्शन के दौरान बेहतर टैलेंट हासिल करने की रस में आगे रहने के लिए भी करती हैं।

## Coming soon: Cars that talk and save lives



**MIRROR TELLS THE TRUTH:** A rearview mirror warns that a vehicle ahead is braking, in a car used in a pilot programme in Michigan

Aaron M Kessler

### Tech tells drivers to stop using mobiles

**Ann Arbor (Michigan):** A driver moves along in traffic, the forward view blocked by a truck or a bend in the road. Suddenly, up ahead, someone slams on the brake. Tires screech. There is little time to react.

Researchers here are working to add time to that equation. They envision a not-too-distant future in which vehicles are in constant, harmonious communication with one another and their surroundings, instantly warning drivers of unseen dangers.

When a motorist brakes quickly, a careless driver runs a red light or a truck bears down unseen in a passing lane, dashboards in nearby cars light up immediately with warnings — providing additional reaction time to avoid a pile-up.

The transportation department announced this week a plan to require in coming years that the technology, so-called vehicle-to-vehicle communication, be installed in all cars and trucks in the US. Transportation secretary Anthony Foxx called it "the next great advance in saving lives".

Google may already be experimenting with its own driverless cars, but the technology being tested in this university town by a group of academic, industry and government researchers could be retrofitted into ordinary cars.

The National Highway Traffic Safety Administra-

Scientists have developed a new facial recognition system that detects when drivers are using their mobile phones and warns them to put the devices down. The software, developed by Brazilian researchers at the Santa Catarina University in Joacaba, has a dashboard camera that issues a warning to drivers when they raise their phone to their ear. The software identifies skin areas and determines whether they represent a face alone, or a face with a hand next to it — a tell-tale sign the driver is making a phone call. PTI

tion estimates vehicle-to-vehicle transmitters will add only about \$350 to the total cost of a vehicle by 2020. By the end of the decade, the typical American vehicle will be part of a network, constantly sharing information as it travels.

At a government-sponsored pilot program in Ann Arbor, being run by the University of Michigan Transportation Research Institute, nearly 3,000 vehicles driven by volunteers are being tested in real-world conditions.

Drivers today can buy cars that monitor blind spots, warn them when they jump a lane and even park themselves. Like any pair of eyes, however, they can warn of only what they see. The Ann Arbor project focuses on hazards even electronic eyes can't spot. NYT NEWS SERVICE

## **IIT's fest page crosses 1.5 Lakh 'likes' on Facebook**

The team from the Indian Institute of Technology, Bombay (IIT-B) responsible for organising the institute's annual technological extravaganza, Techfest, were in a joyous mood on Thursday after the "likes" on the event's Facebook page crossed 1.5 lakh. According to the members of the organising committee, this is reflective of the growing popularity of the event in India and abroad.

Speaking about the landmark, Aman Mantry, media manager for Techfest said that apart from the popularity, it was also indicative of the growing interest among people to know more about what the fest has to offer them this year.

"Even though Techfest preparations were launched only four months ago the number of likes touching 1.5 lakh was something that we had targeted for September or October as last year's team had achieved one lakh likes just before the festival in December," said Mr Mantry.

Throwing light on the importance of achieving the landmark, Mr Mantry said that it acted as an incentive for advertisers, both locally and internationally, to take part in the festival. "Advertisers are the main source of funding for Techfest. This year too we have a huge estimated budget for the festival and hence the 1.5 lakh number is important," he added.

Former Techfest manager Shrey Singh congratulated the current team and said that it would reflect in the achievements of the team members too. "At the end of each academic year, the institute awards achievers and this team is already in line for it," said Mr Singh.